कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Postal R.No.MP/BPL/525/2025-27 RNI No. Raj HIN/2000/3239, डाक प्रेषण का दिन- मंगलवार, बुधवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 जयपुर, प्रकाशन - सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 वर्ष-26 अंक-2 मूल्य-12/- कुल पृष्ठ-12 www.krishakjagat.org पृष्ठ-1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

5

फव्वारा सिंचाई : लाभकारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति

6

पारिजात सुगंध, औषधि और आस्था का अद्भुत संगम

मुख्यमंत्री ने सहकार सदस्यता अभियान का किया शुभारम्भ

सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से देश सहकार से समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। इसी दिशा में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं एवं युवाओं को जोड़ा जाएगा।

श्री शर्मा कांस्टीट्यूशन क्लब में सहकार सदस्यता अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 8 हजार 300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां

15 अक्टूबर तक प्रदेश में चलेगा सहकार सदस्यता अभियान

आयोजित की जा रही हैं। साथ ही, सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पैक्स विहीन 2 हजार 158 ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स एवं जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन्हें भूमि आवंटन का कार्य भी किया जाएगा।

हमारी सरकार सहकारिता से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, मसालों आदि को भी इससे जोड़ने का प्रयास करेगी।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

कृषक जगत की संचालक डॉ. साधना गंगराड़े सम्मानित

मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगूभाई पटेल ने गत दिनों हिन्दी भवन भोपाल में आयोजित एक गरिमामय समारोह में कृषक जगत की संचालक एवं हिन्दी लेखिका संघ की प्रांताध्यक्ष डॉ. साधना गंगराड़े को हिंदी सेवी पुरस्कार से शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्षद्वय श्री रघुनंदन शर्मा एवं श्रीमती रंजना अरगड़े, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. महेश सक्सेना, सप्रे संग्रहालय के संचालक श्री विजय दत्त श्रीधर सहित राष्ट्रभाषा प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

किसानों और इंडस्ट्री की मांगों के अनुरूप ही रिसर्च का मतलब : श्री चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री ने गन्ना अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय परामर्श सत्र को किया संबोधित

नई दिल्ली/भोपाल (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि अनुसंधान तभी सार्थक है जब उसका सीधा फायदा किसानों को मिले। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से गन्ना अनुसंधान के लिए अलग टीम गठित करने को कहा, जो गन्ने की नीतियों और किसानों की व्यावहारिक समस्याओं पर काम करेगी।

पूसा परिसर में आयोजित 'गन्ना अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय परामर्श सत्र' को भोपाल से वर्चुअल संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गन्ने की नई किस्मों में चीनी की मात्रा तो बेहतर है, लेकिन रोग बड़ी चुनौती हैं। मोनोक्रॉपिंग से मिट्टी की उर्वरता और उत्पादन प्रभावित होता है, इसलिए इंटरक्रॉपिंग और रोग-प्रतिरोधी किस्मों पर रिसर्च जरूरी है।

उन्होंने लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने, मैकेनाइजेशन और पानी की बचत पर जोर देते हुए कहा कि 'पर ड्रॉप-मोर क्रॉप' सोच को आधार बनाना होगा। श्री चौहान ने कहा कि एथेनॉल, मोलासेस और अन्य बायो-प्रोडक्ट्स से किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने चीनी मिलों से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। साथ ही कहा कि प्राकृतिक खेती और बायो-प्रोडक्ट्स को भी उर्वरक संकट के समाधान के रूप में देखा जा सकता है।

कार्यक्रम में आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित अनेक विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।

तीनों राज्यों के 27 लाख किसानों को मिली 540 करोड़ पीएम सम्मान निधि की राशि

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने की घोषणा की। यह किस्त विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के उन किसानों के लिए है, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के कृषि मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही किसान समूहों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। तीनों राज्यों के लगभग 2.7 लाख महिला किसानों सहित 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में कुल 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई है।

रबी 2025 के लिए उच्च उत्पादकता वाली गेहूं की नई किस्में

नई दिल्ली (कृषक जगत)। कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग ने रबी 2025 सीजन के लिए नई उच्च उपज और जलवायु सहनशील गेहूं की किस्में जारी की हैं। ये किस्में तापमान में उतार-चढ़ाव, सूखा और गर्मी जैसी परिस्थितियों को सहन कर सकती हैं। कुछ किस्मों में अतिरिक्त गुण भी हैं जैसे गेहूं ब्लास्ट रोग से प्रतिरोधक क्षमता, अधिक प्रोटीन की मात्रा, जिंक की प्रचुरता, चपाती और ब्रेड की बेहतर गुणवत्ता तथा ड्यूरम उत्पादों के लिए उपयुक्तता।

कृषि विभाग का कहना है कि ये किस्में किसानों को बदलती जलवायु परिस्थितियों से बचाव के साथ-साथ बेहतर उपज और गुणवत्ता प्रदान करेंगी। इससे आने वाले वर्षों में देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आमदनी में भी सुधार होगा।

रबी 2025 के लिए जारी जलवायु सहनशील गेहूं की किस्में

किस्म	जोन/उत्पादन परिस्थिति	संभावित उत्पादकता (क्विं./हे.)	औसत उत्पादकता (क्विं./हे.)	विशेषताएं
JKW 261	NWPZ-LS-IR	66.6	51.7	सूखा व गर्मी सहनशील
JKW 296	NWPZ-TS-RI	83.3	56.1	जलवायु सहनशील, बहुउपयोगी
JKW327	NWPZ-IR-ES-HF	87.7	79.4	सूखा व गर्मी सहनशील
JKW 332	NWPZ-IR-ES-HF	83.0	78.3	उच्च प्रोटीन (12.2 प्रतिशत)
HUW 838	NWPZ-TS, RI	77.7	51.3	गेहूं ब्लास्ट रोग प्रतिरोधी
HI 1636	CZ-TS, IR	78.8	56.6	जिंक युक्त (44.4 ppm)
GW 513	CZ-TS, IR	77.4	58.5	चपाती गुणवत्ता (8.36 स्कोर)
MP(JW)1358	CZ-TS, RI	43.6	30.9	सूखा व गर्मी सहनशील
HI 8823 (d)	PZ-TS, RI	65.6	38.5	ड्यूरम उत्पादों के लिए उपयुक्त
DBW 222 (AE)	NEPZ-TS-IR	62.0	48.9	चपाती (7.5) व ब्रेड (8.24) गुणवत्ता
DBW 187 (AE)	CZ-IR-ES-HF	75.4	60.3	उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व व केंद्रीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त

संकेताक्षर – NWPZ – उत्तर पश्चिमी मैदान क्षेत्र; NEPZ – उत्तर-पूर्वी मैदान क्षेत्र; CZ – केंद्रीय क्षेत्र; PZ – प्रायद्वीपीय क्षेत्र; TS – समय पर बोई गई फसल; LS – विलंबित बोई गई फसल; ES – जल्दी बोई गई फसल; IR – सिंचित; RI – सीमित सिंचाई; RF – वर्षा आधारित।

किसानों को मिला दशहरे का तोहफा

गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रु. बढ़कर 2585 रु. प्रति क्विंटल हुआ

रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित

(नई दिल्ली कार्यालय)

नई दिल्ली। दशहरे से ठीक पहले मोदी सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'राष्ट्रीय दलहन मिशन' को मंजूरी दी गई है और साथ ही रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये फैसले किसानों की आय बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता लाने और देश की खाद्य व पोषण सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। बुवाई से पूर्व एमएसपी की जानकारी होने पर किसान को फसल चयन करने में आसानी होती है। क्योंकि उसे पता होता है कि कौन सी फसल कितने रुपए क्विंटल बिकेगी। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2025-26 में रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। इससे विपणन सीजन 2026-27 में खरीदी की जाएगी।

एमएसपी बढ़ाने का फैसला

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, गेहूं समेत रबी फसलों की एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए लागत पर 109 प्रतिशत तक लाभ किसानों को मिलेगा। श्री चौहान ने कहा- कैबिनेट के इन ऐतिहासिक फैसलों से किसानों की आमदनी, सामाजिक सम्मान एवं देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि कुसुम के लिए रु. 600 प्रति क्विंटल की गई है, मसूर के लिए रु. 300 प्रति क्विंटल की गई है। रेपसीड और सरसों, चना, जौ और गेहूं के लिए क्रमशः रु. 250 प्रति क्विंटल, रु.225 प्रति क्विंटल, रु.170 प्रति क्विंटल और रु.160 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पोषण एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय दलहन मिशन' मंजूर किया गया है। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से 350 लाख टन करने का है।

विपणन मौसम 2026-27 के लिए रबी फसलों हेतु एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की घोषणा के अनुरूप है।

3 वर्षों का तुलनात्मक विवरण (रूपए प्रति क्विंटल में)

फसल	2023-24	2024-25	वृद्धि	2025-26
गेहूं	2275	2425	160	2585
जौ	1850	1980	170	2150
चना	5440	5650	225	5875
मसूर	6425	6700	300	7000
सरसों	5650	5950	250	6200
कुसुम	5800	5940	600	6540

फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार कटिबद्ध : कृषि मंत्री

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान शुरू

जयपुर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर खरीफ- 2025 की 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

कृषि मंत्री ने कहा कि पूरे देश में खरीफ- 2025 की 8 करोड़ 71 लाख बीमा पॉलिसियां करवाई गई हैं, जिनमें से 2 करोड़ 16 लाख यानी लगभग 25 प्रतिशत पॉलिसियां राजस्थान की हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को बीमा के प्रति जागरुक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक घर-घर जाकर पॉलिसियों का वितरण किया जा रहा है एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा नवीन कृषि तकनीकों एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो किसान इन शिविरों में पॉलिसी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे अपनी फसल बीमा पॉलिसी संबंधित कृषि पर्यवेक्षक एवं बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि फसल बुआई करने के बाद किसी कारण से फसल नहीं उग पाती है तो ऐसे किसान को बीमित राशि का 25 प्रतिशत मुआवजा दिया जा रहा है। बुआई से कटाई तक विभिन्न प्रकार की आपदाओं एवं फसल कटाई पश्चात सुखाने के लिए खेत में पड़ी फसल में बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवाती वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान झेलना पड़ता है। इन आपदाओं से कृषकों को राहत प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

वरदान साबित हो रही है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रचार-प्रसार और किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान मिल जाने से इस योजना की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि किसानों को इन विकट परिस्थितियों में नुकसान होने पर सरकार द्वारा सहायता मिलने से आर्थिक मजबूती मिलती है, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाते हैं। पॉलिसी वितरण के दौरान किसान पाठशाला के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। बीमा कंपनियों द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर लगभग 32.10 लाख कृषकों को लगभग 2.16 करोड़ पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की आपदा प्रबंधन द्वारा गिरदावरी करके किसानों को नुकसान की भरपाई की जा रही है। कृषि विभाग किसानों की उपज की पैदावार में वृद्धि के हर संभव प्रयास कर रहा है। कृषक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो । दूर-दराज के क्षेत्र, जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां किसान पीएम कुसुम कंपोनेन्ट बी योजना के तहत सोलर पंप लगवाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। जिसमें राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों को खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिये 5 प्रतिशत प्रीमियम अदा करना पड़ता है। फसल बीमा सभी श्रेणी के कृषकों के लिए खरीफ- 2022 से स्वैच्छिक है लेकिन ऋणी कृषकों को योजना से पृथक होने के लिए योजना से जुड़ने के अन्तिम तिथि से सात दिन पूर्व लिखित में आवेदन किया जाना आवश्यक है।

बैठक में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल, आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी सुश्री चिन्मयी गोपाल, अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) श्री गोपाल लाल जाट, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्री एस. एस. शेखावत, अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) श्री अजय कुमार पचौरी, संयुक्त निदेशक कृषि (फसल बीमा) डॉ. जगदेव सिंह सहित विभागीय अधिकारी और कृषक उपस्थित रहे।

पशुपालन मंत्री ने गौशाला संचालकों, पशुपालकों एवं विभाग के अधिकारियों की ली बैठक

गोवंशों को भी गोशाला में भर्ती करवाकर उनकी देखभाल की जाए : श्री कुमावत

जयपुर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बूंदी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गौशाला संचालकों, पशुपालकों एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में पशुपालन मंत्री ने बूंदी जिले में संचालित 6 अपात्र गौशालाओं की तहसीलवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि गौशाला संचालक निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गोवंश की संख्या बढाएं। साथ ही अन्य मूलभूत व्यावस्थाएं सुचारू करें, ताकि उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़कों पर निराश्रित गोवंशों को भी गोशाला में भर्ती करवाकर उनकी देखभाल की जाए। उन्होंने जिले में संचालित पात्र गौशालाओं के संचालकों को वर्तमान में संचालन संबंधी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाएं और मृत गोवंश के उठाव की समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हों। गोशालाओं में पेयजल, छाया, चारा भण्डारण, चार दीवारी की व्यवस्था की जावे।

श्री कुमावत ने मोबाइल वेटरनिटी 1062 हेल्पलाइन, गौशाला विकास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक के पशुओं की हानि होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि, लम्पी रोग की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में पशुपालकों को जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करना ही हम सबका लक्ष्य हैं। गाय न केवल मनुष्य जीवन को बेहतर बनाती है, उससे प्राप्त होने वाला खाद, गो मूत्र, गोबर सहित अन्य सामग्री मनुष्य जीवन के लिए बेहद उपयोगी होती हैं। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत चारागाह भूमि पर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कार्य किया जाए।

पशुपालन मंत्री ने बैठक में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत जिले में हुए कुल पंजीयन, अर्जित लक्ष्यु, प्राप्त लक्ष्य, ग्रामीण सेवा शिविर, पशुओं में विभिन्न रोगों की जांच, बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत घोषित पशु चिकित्सा, उपकेन्द्र की वर्तमान स्थिति, एमएफडी टीकाकरण के तहत गाय व भैंस को किए गए टीकाकरण, सेक्स सोटेड सीमन, पशुधन विकास कार्यक्रम के तहत निर्धारित कार्यक्रम के विपरीत प्राप्त की गई प्रगति, पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, भेड़ निष्क्रमण कार्यक्रम की समीक्षा की।

बैठक में जिला कलक्टर श्री अक्षय गोदारा सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण एवं गौशाला संचालक मौजूद रहें।

बरसात से कटाई के बाद रखी फसल खराब होने पर मिल सकेगा बीमा क्लेम

72 घण्टे में देनी होगी सूचना

जयपुर। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने बताया कि राज्य में वर्तमान में हो रही बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवर्ती वर्षा एवं चक्रवात से कटाई के बाद 14 दिन तक की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी, जिसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घण्टे के भीतर खराबे की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देनी होगी। कृषि विभाग ने बीमा कम्पनियों को प्राप्त सभी इंटीमेशन का तत्काल सर्वे कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

श्री विशाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरान्त खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। असामयिक वर्षा से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके। फसल में हुए नुकसान की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी, नज़दीकी कृषि कार्यालय अथवा सम्बन्धित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते है।

उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों एवं बीमा कम्पनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार बोन्द्रिया द्वारा संदीप शर्मा मे. संदीप इन्टरप्राइजेस, एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित एवं पेपर प्रिंट इंडस्ट्रीज 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, सम्पादक : सुनील गंगराड़े, समन्वयक : रीतेश कोंडले. इस अंक का मूल्य रुपये 12/- वार्षिक शुल्क रुपये 600/- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रं. Raj/HIN/2000/3239

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्द्रिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

जो मनुष्य अपने वचन पर दृढ़ रहता है,
उसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं रहता। - महात्मा गांधी

भावांतर योजना : किसानों या व्यापारियों के हित में !

मध्यप्रदेश में सोयाबीन की फसल खरीदी के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत 3 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हो चुका है तथा सोयाबीन उत्पादक किसान आगामी 17 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे। सरकार ने घोषणा की है कि इसी महीने 24 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी शुरू होगी जो 15 जनवरी तक चलेगी। सरकार ने इस साल सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। अगर किसानों को मंडियों में इससे कम मूल्य मिलता है तो अंतर वाली राशि सीधे किसान के खाते में भेजी जाएगी। पढ़ने और सुनने में भावांतर योजना किसानों के हित में प्रतीत होती है। यदि ऐसा होता तो किसानों के प्रतिनिधि संगठन भावांतर योजना को पूरी तरह असफल बताते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग कर रहे हैं वहीं सरकार योजना को किसानों के हित में बता रही है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि पहले भी भावांतर योजना को लागू किया जा चुका है और पूरी तरह असफल रही है।

संघ का आरोप है कि पिछले वर्षों में लागू की गई भावांतर योजना का करीब ढाई सौ करोड़ रूपये किसानों को भुगतान किया जाना बाकी है। मध्यप्रदेश की अधिकांश मंडियों में नए सोयाबीन की आवक शुरू हो चुकी है और लगभग सभी मंडियों में 5 हजार रूपए से कम भाव पर ही बिक रहा है। जब सरकार ने ही सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है तब किसानों को एमएसपी से कम कीमत मिलने से किसानों का गुस्सा जायज है। किसान सोयाबीन की कीमत 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि जिन किसानों की सोयाबीन की उपज साफ-सुथरी और गुणवत्ता की होगी, उसी को एमएसपी की दर से कम कीमत मिलने पर भावांतर योजना का लाभ मिलेगा यानी यदि सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिकता है तो किसान को वास्तविक विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच का अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

आमतौर पर बाजार और मंडियों में अधिक आवक होने पर कीमतें कम हो जाती हैं जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। लेकिन भावांतर योजना के कार्यांवयन का कटु अनुभव रहा है कि कम ही अवसरों पर कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छू पाती है। इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि व्यापारी जान-बूझकर कीमतें इसलिए बढ़ने नहीं देते क्योंकि वास्तविक कीमत और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई सरकार तो कर ही देगी जिससे किसानों को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत फसल की कीमत तो मिल ही जाएगी। इसी मानसिकता के कारण जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू है, उनकी कीमतों में अन्य फसलों की अपेक्षा कम ही वृद्धि होती है और इसका नुकसान सरकार को भी होता है। सरकार को चाहिये कि सोयाबीन सहित अन्य सभी फसलें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल की गई हैं, उनकी गुणवत्ता के आधार पर खरीदी करना सुनिश्चित करें। फसल की गुणवत्ता के मापदण्ड के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनानी चाहिए ताकि वह बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके। समिति में किसानों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। भावांतर योजना भले ही किसानों के हित के लिए संचालित की जा रही है लेकिन इससे किसानों से ज्यादा व्यापारी वर्ग लाभांवित होगा।

किसानों को तो योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य और विक्रय मूल्य का अन्तर प्राप्त हो जाएगा लेकिन सरकार को व्यर्थ ही करोड़ों रूपये का आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिसूचित उपज कम मूल्य पर न बिके। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित ही अच्छी गुणवत्ता की उपज होने के बावजूद कीमतें न्यूमतम समर्थन मूल्य के बराबर या इससे अधिक कीमत मिल पाएगी। यह तभी हो सकता है जब फसल का उत्पादन बहुत कम हुआ है। भावांतर योजना के तहत पंजीयन और खरीदी का कार्य शुरू हो चुका है इसलिये यह ध्यान रखना होगा कि किसानों को अधिसूचित फसल का कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। कोशिश यह भी करनी होगी कि यदि व्यापारी कम कीमत पर खरीदने की कोशिश करते हैं तो सरकार स्वयं खरीदे और देश में ही खपत के साथ निर्यात के भी प्रयास करे। इससे किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही, सरकार को भी आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि मंडियों में आवक और उसकी कीमत पर नजर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर व्यापारियों को अनावश्यक रूप से लाभ उठाने से रोका जा सके।

देश सहकार से समृद्धि की लिख रहा नई कहानी

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने 'सहकार से समृद्धि' को उतारा धरातल पर

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं और सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की हैं।

पैक्स को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक पंचायत और गांव में दो लाख से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां पांच वर्षों में गठित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के तहत पैक्स स्तर पर गोदाम और अन्न भंडारण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।

किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार है पशुपालन

श्री शर्मा ने कहा कि पशुपालन किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार होता है। इनके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना संचालित की जा रही है। इसके जरिए डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा के लिए प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित की जा रही हैं। किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने का काम किया गया है। प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता एवं देवास परियोजना के विस्तार को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पांच वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य की प्राप्ति में 91 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं।

पशुपालन एवं डेयरी व गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सहकारिता का भाव 'एक सब के लिए, सब एक के लिए' में निहित होता है। सहकार सदस्यता अभियान के तहत डेयरी क्षेत्र में लक्ष्य से ज्यादा नए सदस्य बनाए जाएंगे। इस अभियान में अधिक से अधिक महिलाओं को सदस्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए लगभग 700 करोड़ रुपये से अधिक की बजट सौगातें दी हैं। आरसीडीएफ द्वारा दूध से बनने वाले उत्पादों में वृद्धि के साथ ही शुद्धता और गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए सरस के विभिन्न उत्पादों की डिमांड में निरंतर वृद्धि हो रही है।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता गतिविधियों में गति आई है। केन्द्रीय सहकारिता विभाग के नवाचारों को अपनाकर उनके क्रियान्वयन की सफलता से राजस्थान देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य किया। वहीं, प्रदेश में भी राज्य सरकार ने प्रथम बजट में ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि देने की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए प्रदेश की हजारों पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। दीर्घकालीन ऋण देने वाला भूमि विकास बैंक मजबूत बना है। अन्न भंडारण योजना के तहत लगभग 700 गोदामों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दौसा की श्रीरामपुरा व बडीयाल खुर्द नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति को गठन के प्रमाण पत्र एवं चित्तौड़गढ़ की सुखवाड़ा व कोटा की रामराजपुरा भूमिहीन ग्राम सेवा सहकारी समिति को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र सौंपे। सहकारिता विभाग की ओर से श्री शर्मा को एपेक्स बैंक की 1.28 करोड़ रुपये की वर्ष 2024-25 की लाभांश राशि तथा कॉनफेड की 21.73 लाख रुपये की वर्ष 2023-24 की लाभांश राशि के प्रतीकात्मक चैक सौंपे गए। इस दौरान उन्होंने सहकार सदस्यता अभियान से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव एवं पंजीयक सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल, आरसीडीएफ एमडी श्रीमती श्रुति भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में सहकारिता सदस्य उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता को बनाया विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर इसे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया। वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को 6 हजार रुपये हर साल दिए जाते हैं। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 7 हजार 54 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अतिरिक्त 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष सम्मान राशि दे रही है। इसके तहत किसानों को अब तक 1 हजार 355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है।

सहकारिता से गांव-गांव और जन-जन हो रहा सशक्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता में सभी व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। यह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन-जन सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने लगभग 77 लाख से अधिक किसानों को 42 हजार 765 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण, 2 लाख 48 हजार नए कृषकों को 433 करोड़ रुपये के फसली ऋण, 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपये के आजीविका ऋण वितरित किए है। साथ ही, अन्न भंडारण योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले के घमूड़वाली पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण यूनिट और कस्टम हायरिंग केंद्र शुरू किए हैं। इसी तरह, सहकारी बैंको द्वारा करीब 7 हजार किसानों तथा लघु उद्यमियों को 246 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण भी वितरित किए गए हैं।

फव्वारा सिंचाई : लाभकारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति

● डॉ. राजेश गुप्ता ● डॉ. जी.एस. चुण्डावत
● डॉ. निशिथ गुप्ता
● डॉ. एस.पी. त्रिपाठी ● श्री संतोष पटेल
rajgupta171@gmail.com

कृषि एवं पशुपालन में जल एक महत्वपूर्ण उत्पादन कारक है। इन कारकों की मात्रात्मक वृद्धि एवं इनकी प्रयोग दक्षता बढ़ाने में भी जल काफी सहायक होता है। देश में कुल उपलब्ध जल का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा कृषि में सिंचाई के रूप में प्रयुक्त होता है। जलवायु परिवर्तन, मानसूनी वर्षा में आ रही लगातार गिरावट एवं अनियमितता की वजह से जल की घटती उपलब्धता तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बढ़ती मांग भविष्य में जल की भारी कमी की तरफ संकेत करते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक कृषि में जल की कमी उपलब्धता घटकर 68 प्रतिशत तक आने की आशंका है। नीति आयोग की रिपोर्ट में देश में जल की भयावह स्थिति के बारे में बताया गया है एवं अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी कृषि में जल की भयावह स्थिति के बारे में बताया गया है। अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कृषि में जल की खपत को 50 प्रतिशत से नीचे लाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। खेती में सिंचाई के लिए भूजल का लगभग एक तिहाई हिस्सा उपयोग किया जाता है।

भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण इसके स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। सिंचाई की परंपरागत प्रवाह विधि में अधिक जल खपत के कारण भी जल की उपयोग दक्षता पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र में सरकारी एवं निजी स्तरों पर अथक प्रयास के बावजूद अभी भी देश के शुद्ध कृषि क्षेत्रफल के आधे से कम (लगभग 49 प्रतिशत) हिस्से में सिंचाई सुविधा सृजित की जा सकी है। शेष बुआई क्षेत्रफल मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है। जलवायु परिवर्तन का असिंचित (बारानी) क्षेत्रों पर सर्वाधिक असर होता है। एक अनुमान के अनुसार बारानी फसलों से प्राप्त वार्षिक आमदनी सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा 25-30 प्रतिशत कम होती है। ऐसी स्थिति में सिंचाई की उन्नत विधियों (फव्वारा एवं टपक) के तहत अधिक कृषि क्षेत्रफल को लाने की आवश्यकता है। इससे उपलब्ध जल का समुचित एवं लाभकारी प्रयोग हो सकेगा तथा प्रति बूंद अधिक उपज एवं आमदनी प्राप्त की जा सकेगी। अतएव कृषि में जल की उपलब्धता बनाये रखने, अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई करने तथा लागत में कमी लाने के लिए फव्वारा सिंचाई विधि खाद्यान्न फसलों के लिए एक उचित विकल्प है। इस सिंचाई पद्धति में जल को छिड़काव के रूप में फसलों को दिया जाता है। इससे जल पौधों पर बारिश की बूंदों की तरह पड़ता है एवं खेत में जल भराव भी नहीं होता है। इस विधि से सिंचाई भूमि के ढलान के अनुरूप की जा सकती है एवं मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। सिंचाई की इस पद्धति में पौधों को समान मात्रा में जल मिलता है, जिससे उनकी समान वृद्धि से अधिक उत्पादकता सुनिश्चित होती है। अनाज फसलों के अतिरिक्त दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए भी यह विधि बहुत उपयोगी है। इन फसलों में कम जल की आवश्यकता होती है।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करती है। इस पद्धति में दो सिंचाई विधियां-फव्वारा तथा टपक (बूंद-बूंद) प्रचलित हैं। जल की घटती उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्रों में जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को मांग-प्रबंधन रणनीति के तौर पर वर्ष 2005-06 में एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना की समीक्षा बैठकों में समय के साथ इसमें बदलाव किये गये। वर्ष 2010 में उपरोक्त स्कीम को 'सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन' और वर्ष 2014 में फिर इसे 'सतत कृषि में राष्ट्रीय मिशन' के अंतर्गत प्रक्षेत्र स्तर पर जल प्रबंधन के रूप में शुरू किया गया। वर्तमान में सूक्ष्म सिंचाई एवं सिंचाई की अन्य योजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015) के तहत समाहित कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 'हर खेत को जल' तथा 'प्रति बूंद अधिक उपज' प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई कार्यक्रम के लागू होने के बाद के वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्रफल बढ़कर 9.2 मिलियन हेक्टर हो गया है। यह इस विधि क तहत लाये जाने वाले संभावित क्षेत्रफल (69.5 मिलियन हेक्टर) का लगभग 13 प्रतिशत है।

फव्वारा सिंचाई पद्धति की सीमायें

फव्वारा सिंचाई पद्धति की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। बिजली की अधिक आवश्यकता और उपकरण की कीमत अधिक होती है। वर्गाकार अथवा आयताकार खेत के लगभग 10-2% भाग की सिंचाई नहीं हो पाती है। वर्गाकार और आयताकार खेत की सिंचाई के लिए सेंटर-पाइवट सिस्टम में आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए अब लैटरल-मूव सिस्टम विकसित किया गया है। यह सिंचाई पद्धति लैटरल-मूव सिस्टम का बना होता है जो खेत में ऊपर-नीचे घूमता रहता है।

फव्वारा सिंचाई पद्धति के लाभ

- सतही सिंचाई में पानी खेत तक पहुँचने में 15-20 प्रतिशत दूर तक अनुपयोगी रहता है। नहर के पानी से यह हानि 30-50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है और सतही सिंचाई में एक सा पानी नहीं पहुँचता जबकि फव्वारा सिंचाई से सिंचित क्षेत्रफल 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है अर्थात् इस विधि से सिंचाई करने पर 25-50 प्रतिशत तक पानी की सीधे बचत होती है।
- जब पानी वर्षा की भांति छिड़का जाता है तो भूमि पर जल भराव नहीं होता है जिससे मिट्टी की पानी सोखने की दर में वृद्धि होती है और कम पानी के बहने से हानि नहीं होती है।
- जिन जगहों पर भूमि ऊंची-नीची रहती है वहाँ पर सतही सिंचाई संभव नहीं हो पाती और उन जगहों पर फव्वारा सिंचाई वरदान साबित होती है।
- फव्वारा सिंचाई अधिक ढाल वाली तथा ऊंची-नीची जगहों के लिए सर्वोत्तम विधि है। इन जगहों पर सतही विधि से सिंचाई नहीं की जा सकती है।
- इस विधि से सिंचाई करने पर मृदा में नमी का उपयुक्त स्तर बना रहता है जिसके कारण फसल की वृद्धि उपज और गुणवत्ता अच्छी रहती है।
- इस विधि में सिंचाई के पानी के साथ घुलनशील उर्वरक, कीटनाशी तथा जीवनाशी या खरपतवारनाशी दवाओं का भी प्रयोग आसानी से किया जा सकता है।
- पानी की कमी, सीमित पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सतही सिंचाई की अपेक्षा फव्वारा सिंचाई पद्धति से दुगना से तीन गुना क्षेत्रफल सिंचित किया जा सकता है।
- पाला पड़ने से पहले फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने पर तापक्रम बढ़ जाने से फसल का पाले से नुकसान नहीं होता है।

फव्वारा सिंचाई पद्धति में रखरखाव एवं सावधानियाँ

फव्वारा सिंचाई के प्रयोग के समय एवं प्रयोग के बाद परीक्षण कर लें और कुछ मुख्य सावधानियाँ रखने से सेट अच्छी तरह चलता है। जैसे - प्रयोग होने वाला सिंचाई जल स्वच्छ तथा बालू एवं अत्यधिक मात्रा घुलनशील तत्वों से युक्त हो तथा उर्वरकों, फफूंदी, खरपतवारनाशी आदि दवाओं के प्रयोग के पश्चात सम्पूर्ण प्रणाली को स्वच्छ पानी से सफाई कर लें। प्लास्टिक वाशरों को आवश्यकता अनुसार निरीक्षण करते रहें और बदलते रहें। रबर सील को साफ रखें तथा प्रयोग के बाद अन्य फिटिंग भागों को अलग कर साफ करने के उपरान्त शुष्क स्थान पर भण्डारित करें।

सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंतर्गत फव्वारा सिंचाई जल की मांग-आपूर्ति के बीच अंतर कम करने एवं इसकी उपयोग दक्षता बढ़ाने का एक उचित विकल्प है। पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रफल में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए सिंचाई की फव्वारा विधि को व्यापक स्तर पर अपनाने इसमें सुधार और किसानों के बीच इसके प्रचार-प्रसार के लिए और अधिक समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

पारिजात

सुगंध, औषधि और आस्था का अद्भुत संगम

- डॉ. दीपक हरि रानडे
- डॉ. मनोज कुरील
- डॉ. स्मिता अग्रवाल

'पारिजात' वृक्ष सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि सुगंध, औषधि और संस्कृति का अनोखा उपहार है।

इस वृक्ष के सफेद फूलों की नारंगी झलक जब रात में खिलकर सुबह ज़मीन पर बिछ जाती है, तो पूरा वातावरण सौंदर्य और सुगंध से भर जाता है। यही कारण है कि इसे लोग न केवल प्रकृति का चमत्कार मानते हैं, बल्कि पूजा और श्रद्धा से भी जोड़ते हैं।

औषधीय और कृषि महत्व

पारिजात की पत्तियाँ और फूल कई रोगों की औषधि हैं। आयुर्वेद में इसका उपयोग बुखार, जोड़ों के दर्द, मलेरिया और त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। इसके फूलों से प्राकृतिक रंग भी बनाया जाता है, जो कपड़ों और खाद्य उत्पादों में काम आता है। सिर्फ औषधि ही नहीं, यह वृक्ष किसानों और पर्यावरण के लिए भी वरदान है। इसकी खुशबू और फूल मधुमक्खियों व तितलियों को आकर्षित करते हैं, जिससे आसपास की फसलों में परागण बढ़ता है और जैव विविधता भी सुरक्षित रहती है।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

शास्त्रों में पारिजात का विशेष उल्लेख है। कहा जाता है कि यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ और भगवान कृष्ण ने इसे द्वारका में लगाया था। आज भी इसके फूल विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा में चढ़ाए जाते हैं। खासकर नवरात्र और शरद पूर्णिमा पर इसकी मांग बहुत रहती है।

रात को ही क्यों खिलते हैं फूल?

पारिजात के फूलों का रहस्य भी कम रोचक नहीं है। ये फूल रात को खिलते हैं क्योंकि इनके मुख्य परागणकर्ता रात में सक्रिय कीट-पतंगे होते हैं। ठंडी और नमी वाली रात में इसकी सुगंध दूर तक फैलती है। सुबह होते ही फूल ज़मीन पर गिर जाते हैं, ताकि पौधा अपनी ऊर्जा और नमी बचा सके। यही झरे हुए फूल लोगों की पूजा और रंग बनाने में काम आते हैं।

जैव विविधता और प्रेरणा

यह पारिजात वृक्ष न सिर्फ छात्रों के लिए अध्ययन और शोध का विषय है, बल्कि यह उन्हें प्रकृति से जुड़ाव और संरक्षण की प्रेरणा भी देता है। इसकी छाँव में बैठने वाला हर व्यक्ति एक अद्भुत शांति और ताजगी का अनुभव करता है। सचमुच, पारिजात सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि प्रकृति, आस्था और विज्ञान का सुंदर संगम है।

घोड़ा नीम (बकाइन)

जैव विविधता और बहुउपयोगिता का साथी

कृषि महाविद्यालय के हरे-भरे परिसर में वर्षों से खड़ा घोड़ा नीम का विशाल वृक्ष न केवल छात्रों और शिक्षकों को छाया देता है, बल्कि जैव विविधता और उपयोगिता का एक जीवंत उदाहरण भी है। आमतौर पर इसे 'बकाइन' कहा जाता है। यह वृक्ष दिखने में आकर्षक होने के साथ-साथ पर्यावरण, कृषि और औषधि - तीनों क्षेत्रों में उपयोगी साबित होता है।

नीम और घोड़ा नीम दोनों के औषधीय व कीटनाशक गुण होते हैं, लेकिन इनमें कुछ फर्क है। घोड़ा नीम की पत्तियाँ बड़ी और हल्की हरी होती हैं तथा स्वाद में नीम की तरह बहुत कड़वी नहीं होतीं। इसके फूल बैंगनी-गुलाबी रंग के होते हैं और फल छोटे बेर जैसे गोल होते हैं। वहीं साधारण नीम के फूल सफेद और फल अंडाकार होते हैं। औषधीय दृष्टि से साधारण नीम अधिक प्रभावी है, पर घोड़ा नीम भी हल्के कीटनाशक और औषधीय उपयोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण जीवन से जुड़ा साथी

गाँवों में आज भी लोग इसके पत्तों का उपयोग अनाज भंडारण में करते हैं, ताकि कीड़े न लगें। खेतों में इसे छायादार वृक्ष के रूप में लगाया जाता है। इसके फल और पत्तियाँ थोड़ी मात्रा में पशुओं के चारे के काम भी आती हैं। लकड़ी हल्की लेकिन टिकाऊ होती है, जिससे ग्रामीण इलाकों में फर्नीचर, खिलौने और कृषि उपकरण बनाए जाते हैं।

गाँव की दादी-नानी अक्सर इसके छाल का काढ़ा बुखार और पेट की तकलीफ में देती थीं। पत्तियों का लेप चर्म रोगों और फोड़े-फुंसियों पर लगाया जाता है। वहीं इसके फूल और फल मधुमक्खियों, पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत हैं, जिससे परागण और पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है।

सावधानी भी ज़रूरी

जहाँ इसके कई फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं। इसके फल और बीज अधिक मात्रा में खाने पर विषैले हो सकते हैं, इसलिए इन्हें पशुओं को बहुत सोच-समझकर दिया जाता है। इसकी जड़ें आसपास के पौधों के पोषक तत्व खींच लेती हैं, जिससे पास की फसलें प्रभावित हो सकती हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

वैज्ञानिक दृष्टि से भी घोड़ा नीम में कई संभावनाएँ छिपी हैं। इसके पत्तों और फलों से जैविक कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। इसके औषधीय गुणों का गहन परीक्षण किया जा सकता है। जैव विविधता संरक्षण, परागण प्रणाली और मिट्टी की सेहत पर इसके प्रभाव का अध्ययन भी कृषि अनुसंधान को नई दिशा दे सकता है। कुल मिलाकर, घोड़ा नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन का साथी, प्रकृति का संरक्षक और आने वाले समय की वैज्ञानिक खोजों का आधार है।

पशु स्वास्थ्य की ढाल - समय पर टीकाकरण

• डॉ. महेन्द्र सिंह मील • डॉ. श्रुति गर्ग
पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानिया, वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुधन किसानों की रीढ़ है। दूध, मांस, अंडे, ऊन और गोबर जैसे उत्पाद न केवल किसानों की आय बढ़ाते हैं, बल्कि पोषण और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करते हैं। लेकिन जब पशु बीमार पड़ते हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है, कभी-कभी जान का नुकसान भी हो जाता है। इन रोगों से बचाव का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है समय पर टीकाकरण। टीकाकरण को पशु स्वास्थ्य की 'ढाल' कहा जा सकता है, क्योंकि यह पशुओं को गंभीर और संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखता है।

टीकाकरण की आवश्यकता

रोगों से बचाव: टीकाकरण के बाद पशु की शरीर प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बढ़ती है और वह रोगों से लड़ने में सक्षम होता है।

उत्पादन क्षमता में वृद्धि: स्वस्थ पशु अधिक दूध, मांस और अंडे देते हैं।

आर्थिक बचत: रोग लगने के बाद इलाज में ज्यादा खर्च आता है, जबकि टीका सस्ता और सुरक्षित उपाय है।

रोगों का प्रसार रोकना: संक्रामक रोग जैसे खुरपका-मुंहपका और गलघोटू तेजी से फैलते हैं। टीकाकरण से पूरे झुंड और गाँव सुरक्षित रहते हैं।

मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा: कुछ रोग जैसे ब्रूसेलोसिस और रेबीज पशुओं से इंसानों में भी फैलते हैं। टीकाकरण से जूनोटिक रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

सामान्य पशु रोग जिनमें टीकाकरण आवश्यक है

खुरपका-मुंहपका : यह गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक संक्रामक रोग है। इसमें पशु के मुंह, जीभ और खुरों में छाले पड़ जाते हैं जिससे वह खाना-पीना छोड़ देता है और दूध उत्पादन अचानक कम हो जाता है।

गलघोटू : यह रोग वर्षा ऋतु में अधिक होता है। इसमें पशु को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई और गले में सूजन हो जाती है, जिससे अचानक मौत हो सकती है।

काला ज्वर: यह रोग विशेषकर 6 माह से 2 वर्ष तक की उम्र के बछड़ों में होता है। मांसपेशियों में सूजन और दर्द के कारण पशु लंगड़ाने लगता है और अक्सर मृत्यु हो जाती है।

ब्रूसेलोसिस: यह रोग मुख्यतः गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है। यह मनुष्यों में भी फैल सकता है, इसलिए इसका टीकाकरण बहुत जरूरी है।

रेबीज (हाइड्रोफोबिया): पागल कुत्ते के काटने से होने वाला यह रोग घातक है। पशुओं और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करता है। टीकाकरण से इसकी रोकथाम संभव है।

टीकाकरण पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि दोनों के लिए वरदान है। समय पर टीका लगवाकर हम न केवल अपने पशुओं को रोगमुक्त रखते हैं, बल्कि पूरे गाँव और समाज को सुरक्षित करते हैं। याद रखें - 'टीकाकरण ही है पशु स्वास्थ्य की सच्ची ढाल।'

पशु टीकाकरण कैलेंडर

रोग	टीकाकरण की आयु/समय	टीकाकरण की आवृत्ति	विशेष टिप्पणी
खुरपका-मुंहपका	सभी उम्र के पशु- मार्च/अप्रैल एवं सितंबर/अक्टूबर	वर्ष में 2 बार	पूरे झुंड को एक साथ टीका लगाएँ।
गलघोटू	सभी उम्र के पशु - बरसात से पहले (मई/जून)	वर्ष में 1 बार	खासकर गाय-भैंस में अनिवार्य।
काला ज्वर	6 माह से 2 वर्ष तक के बछड़े बरसात से पहले (मई/जून)	वर्ष में 1 बार	बछड़ों में अधिक आवश्यक।
ब्रूसेलोसिस	4-8 माह की मादा बछड़ी	जीवन में केवल 1 बार	गर्भवती और दूध देने वाली गाय/भैंस को न लगाएँ।
रेबीज	जोखिम वाले क्षेत्रों में (कुत्ते/सियार प्रकोप)	वर्ष में 1 बार	मनुष्यों के लिए भी सुरक्षा देता है।

किसानों को चाहिए कि नजदीकी पशु चिकित्सालय से परामर्श लेकर अपने पशुओं का टीकाकरण कैलेंडर बनवाएँ।

किसानों को होने वाले लाभ

- **उच्च दूध उत्पादन:** रोगों से मुक्त पशु अधिक दूध देते हैं।
- **बच्चों की मृत्यु दर कम:** नवजात बछड़े और मेमने सुरक्षित रहते हैं।
- **बीमारी का खतरा घटे:** पशुओं का इलाज, दवा और मजदूरी पर होने वाला खर्च बचे।
- **झुंड की सुरक्षा:** एक पशु बीमार हुआ तो पूरा झुंड खतरे में आता है। टीकाकरण से यह खतरा टलता है।
- **किसान की आय में वृद्धि:** स्वस्थ पशु किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं।

किसानों के लिए सुझाव

- सभी पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएँ।
- टीकाकरण के समय पशु पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए।
- गर्भित पशुओं और छोटे बच्चों में कुछ टीके नहीं लगते, इसलिए डॉक्टर की सलाह लें।
- टीकाकरण के बाद हल्का बुखार या सूजन आना सामान्य है। घबराएँ नहीं।
- टीकाकरण के साथ-साथ कीड़ा मुक्ति भी समय पर कराएँ।

भारत का एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए नई उम्मीद

बारिश की चिंता और खेती का फैसला

खेती में सबसे बड़ी चिंता हमेशा यही रहती है कि बारिश कब होगी और कितनी होगी। खासकर खरीफ की खेती तो पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है। अगर किसान को समय से पहले पता चल जाए कि मानसून कब आएगा, तो वह यह तय कर सकता है कि कौन-सी फसल बोनी है, कितनी बोनी है और कब बोनी है।

अब एआई से पहले ही मिलेगी खबर

इस साल भारत सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी पहल की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बने मौसम पूर्वानुमान को सीधे किसानों तक पहुँचाया गया। कृषि मंत्रालय ने m-Kisan पोर्टल के ज़रिए 13 राज्यों के लगभग 3.8 करोड़ किसानों को SMS भेजे। खास बात यह रही कि यह जानकारी मानसून आने से करीब चार हफ्ते पहले ही दी गई। यानी किसान पहले से ही खरीफ की योजना बना सके।

समय पर मदद, सही फैसला

मानसून इस बार जल्दी आ गया, लेकिन बीच में करीब 20 दिन तक बारिश थम गई। ऐसी स्थिति में किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन एआई आधारित पूर्वानुमान ने इस रुकावट को समय पर पहचान लिया। सरकार ने हर हफ्ते किसानों को अपडेट भेजे और लगातार जानकारी दी, जब तक कि उनके क्षेत्र में अच्छी बारिश शुरू नहीं हो गई।

मौसम पूर्वानुमान में क्रांति

एआई ने मौसम की भविष्यवाणी को नई दिशा दी है। साल 2022 से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ और अब यह तकनीक किसानों के लिए किसी वरदान की तरह है। गूगल का Neural GCM मॉडल और यूरोप का Artificial Intelligence Forecasting System (AIFS), दोनों ने पारंपरिक पूर्वानुमानों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और मानसून की सही शुरुआत का पता लगाया।

किसानों की भाषा में संदेश

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि किसानों को भेजे गए संदेश आसान भाषा में थे। उन्हें तकनीकी शब्दों के बजाय सीधे-सीधे बताया गया कि क्या करना है—बीज डालना है, इंतजार करना है या सिंचाई की तैयारी करनी है। इससे किसान बिना किसी उलझन के तुरंत निर्णय ले पाए।

विशेषज्ञों की राय

कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ी है और एआई किसानों को बदलते हालात में ढलने में मदद करेगा। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने इसे किसानों के लिए बेहद अहम पहल बताया। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर ने कहा कि भारत ने करोड़ों किसानों तक एआई का लाभ पहुँचाकर दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है।

किसानों के लिए नया भरोसा

कुल मिलाकर, अब किसान अटकलबाज़ी के बजाय एआई की सटीक जानकारी पर भरोसा कर सकेंगे। यह पहल खेती को और सुरक्षित, समझदार और फायदेमंद बनाएगी। किसानों के लिए यह एक नया भरोसा है—अब मानसून की बारिश कब होगी, इसकी खबर उन्हें पहले से मिल जाएगी।

समस्या -समाधान

समस्या– सर्पगन्धा की खेती में इच्छुक हूं, परामर्श देने की कृपा करें।

– अम्बिका पटेल

समाधान– *सर्पगन्धा की खेती के लिये नम*

तथा हल्के गर्म मौसम की आवश्यकता होती है।

● इसकी जड़ें औषधि के रूप में उपयोग में आती है।

● अच्छे निकास वाली बलुई से भारी दोमट मिट्टी जिसका पी.एच. 8 से कम हो उपयुक्त रहता है। 4.6 से 6.2 पी.एच. अधिक उपयुक्त।

● धूप व आंशिक छाया वाले खेत अधिक उपयुक्त जहां पाला पड़ता हो वहां न लगायें।

● 25 से 30 टन गोबर की अच्छी सड़ी खाद अवश्य डालें।

जाति–सर्पगंधा– 1, (कृषि महाविद्यालय, इंदौर में विकसित)।

● उत्पत्ति– बीज, जड़ों व तनों से।

● बीज बोने का समय– मई मध्य, 6 माह से पुराने बीज का अंकुरण 15–20 दिन बाद।

● बीज नर्सरी में बोयें। एक हेक्टर के लिए 500 वर्ग मीटर नर्सरी लगायें, बीज मात्रा 5.5 किलोग्राम।

● रोपड़ 4–6 अवस्था में, मुख्य जड़ काट कर।

● जड़ों से बुआई– मार्च से जून तक 100 किलोग्राम जड़ें (10–12 से.मी.) प्रति हेक्टर।

● उपज– 25 क्विंटल जड़ें प्रति हेक्टर 18 माह में।

समस्या– गेहूं में पहली बार नींदा नियंत्रण के लिए नींदानाशक का प्रयोग करना चाहता हूं, परामर्श दीजिए।

– संदीप साय

समाधान– *● गेहूं में दोनों सकरी तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार/ नींदा आते हैं।*

● संकरी पत्ती वाले नींदा में जंगली जई, चिरैया बाजरा, दूब व कांस प्रमुख हैं। चौड़ी पत्ती में बथुआ, दूधी, हिरनखुरी, कटेली, सेजी, कृष्णनील, अकरी आदि प्रमुख हैं।

● आपके खेत में कौन –कौन से नींदा की बहुलता है। उस आधार पर नींदानाशक का चयन करना होगा।

● यदि दोनों प्रकार के नींदा आपके गेहूं के खेतों में आते हैं तो पेन्डामेर्थिन 30 ईसी के 3.3 लीटर को 500–600 लीटर पानी में घोल कर बुआई के तुरन्त बाद से 3 दिन के अंदर से छिड़काव करें। यह संकरी तथा चौड़ी दोनों प्रकार की नींदा को नियंत्रित करेगा।

● यदि आपकी फसल में संकरी पत्ती वाले नींदा हो तो आइसोप्रोट्यूरॉन 75 की एक किलो ग्राम– 500–600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें।

● यदि दोनों प्रकार के नींदा आते हो तो आइसोप्रोट्यूरान में 250 ग्राम 2–4 डी सोडियम लवण 30 प्रतिशत मिलाकर बुआई के 30 दिन के अंदर छिड़कें। इसके अतिरिक्त सल्फोसल्फ्यूरॉन 25 ग्राम प्रति हेक्टर का भी उपयोग किया जा सकता है।

नींदानाशक के उपयोग में निम्न सावधानी अवश्य रखें।

● छिड़कते समय भूमि में पर्याप्त नमी अवश्य रहे।

● फ्लेट फेन या प्लेट जेट नोजल का ही पयोग करें।

● स्प्रे पूरे क्षेत्र में अच्छी तरह व एक समान हो।

● स्प्रे खुले सूखे मौसम में करें।

समस्या– गेहूं की फसल में दीमक बहुत नुकसान पहुंचाती है। रोकथाम के उपाय बतायें।

– सुरेश कुमार

समाधान– *● खेत के आसपास दीमक के बमीठों को खोदकर रानी दीमक को नष्ट करने का प्रयत्न करें। पूरे गांव में सामूहिक रूप से यह*

कार्य किया जाये तो अच्छे व दूरगामी परिणाम मिलेंगे।

● गेहूं बोने के पूर्व बीज को क्लोरोफायरीफॉस 20 ई.सी. के 5 मि.ली. या थायीमोक्जेम 75 डब्ल्यू. एस. के 5 मि.ली. या फेप्रोनिक 5 एफ.एस. के 2 मि.ली. को 1–3 लीटर पानी में घोलकर प्रति किलो बीज मान से उपचारित कर लगायें।

● खड़ी फसल में दीमक नियंत्रण के लिये क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. 1 लीटर प्रति हेक्टर के मान से सिंचाई के पानी के साथ दें।

समस्या– मैं पालक लगाना चाहता हूं, कृपया विधि तथा अच्छी जातियां बतायें।

– सुधाकर राव

समाधान– *आप पालक लगाना चाहते हैं यह समय पालक लगाने के लिये उपयुक्त है आप निम्न उपाय करें–*

● सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है।

● जातियों में पूसा भारती, पूसा हरिता, अलग्रीन, पूसा ज्योति तथा जोबनेर ग्रीन।

● बीज की मात्रा 20–30 किलो बीज/हे. पर्याप्त होगी।

● उर्वरकों में 25 किलो यूरिया, 40 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश/हे. की दर से डालें।

● बुआई का उचित समय सितम्बर से दिसम्बर।

● बुआई के 3–4 सप्ताह बाद से कटाई शुरू की जा सकती है। तथा 15–20 दिनों के अंतर से बराबर कटाई की जाये।

समस्या– मैं अजबाईन लगाना चाहता हूं, कृषि तकनीकी से अवगत करायें।

– जसवंत गौड़

समाधान– *आप मसाला फसल अजबाईन लगाना चाहते हैं खेती से अधिक लाभ कमाने के लिये कुछ नया करने की जरूरत है। आपके पड़ोस सुल्तानपुर में हल्दी की खेती बहुत की जाती रही है। आप निम्न तकनीक का पालन करें।*

● भूमि जिसमें अजबाईन लगाना है में जल

प्रबंध अच्छा हो।

● 3–4 किलो बीज/हे. की दर से लगता है बीज का उपचार 2 ग्राम थाईरम/ किलो बीज का करें।

● बीज में खाद या राख मिलाने से बीज में अच्छा अंतर आ जाता है और सघनता ठीक हो जाती है।

● बुआई का उचित समय अक्टूबर–नवम्बर है।

● उन्नत जातियों में लाभ सलेक्शन 1, लाभ सलेक्शन 2, आर.एच. 40 इत्यादि हैं। इसके अलावा एन.डी.30, एन.पी. 151, एन.पी. 66, एन.पी. 79, एन.पी. (जे.) 8 तथा एन.पी. (जे)15 प्रमुख हैं। जो कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में विकसित की गई हैं।

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान

कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100,2554864

कृषक जगत
बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक
रु. 95

कोड : 016

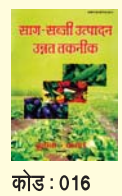

सब्जियों में पौध संरक्षण
रु. 75

कोड : 017

मशरूम एक लाभ अनेक
रु. 45

कोड : 019

मिर्च की उन्नत खेती
रु. 55

कोड : 020

केला उत्पादन
रु. 70

कोड : 025

गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण
रु. 75

कोड : 027

पपीता
रु. 55

कोड : 031

अदरक
रु. 55

कोड : 032

फलों की खेती
रु. 75

कोड : 040

सजाएं फूलों से बगिया
रु. 65

कोड : 041

घर की बगिया
रु. 95

कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/ मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम ____________
ग्राम ________ पोस्ट ________ तह. ________
जिला ________ फोन/मोबा. ________
कुल राशि ________ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या ________
संलग्न ड्राफ्ट नं. ________ मनी आर्डर रसीद क्र. ________ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

स्वास्थ्य/शिक्षण

सावधान रहें, चोरी से आने वाली सर्दी से...

सर्दी आ गई है लेकिन तापमान में अभी कोई विशेष अंतर नहीं आया है। इसकी वजह मौसम की मौजूदा विसंगति भी है। लेकिन वजह चाहे जो हो, तापमान बढ़ते ही लोग सर्दी को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। बस तभी यह धीरे–धीरे आती हुई सर्दी चुपके से कोल्ड और फ्लू के रूप में खतरनाक हमले शुरू कर देती है। सवाल है, इससे कैसे बचे रहें। तो चुपके से धावे बोलने वाली इस कोल्ड से बचने के बेहतर तरीके ये हैं– ● जितनी ज्यादा बार संभव हो अपने हाथ धोएं।

● अगर कोई कोल्ड या फ्लू से पीड़ित है तो उससे हाथ मिलाने, वायरसग्रस्त सतह जैसे दरवाजे के हैंडिल आदि छूने, फिर उन्हीं हाथों से अपनी आंखें मलने की वजह से कोल्ड होता है।

● रोजाना विटामिन–सी लें। इससे दस्तक देती गर्मी में भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उपचार में भी तेजी आती है। ● ज्यादा तनाव से बचें क्योंकि तनाव आपके जिस्म में जो इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता है उसमें बाधक बनता है। ● रोजाना तीस मिनट तक कसरत करने से भी कोल्ड और फ्लू से लड़ने में मदद मिलती है।

● कोल्ड और फ्लू में आमतौर पर भेद करना मुश्किल है। लेकिन फ्लू जरा

तेजी से आता है और कोल्ड की तुलना में जिस्म को ज्यादा तोड़ देता है। इसी से इसके फर्क को समझ लें।

● इसके अन्य लक्षणों में हैं– टांगों में दर्द, तेज तापमान का अहसास और पूरे जिस्म में थकान। यह बहुत जल्दी दूसरे लोगों में भी फैलता है। कहने का मतलब यह कि यह बेहद संक्रामक है।

इससे बचने के तरीके हैं– ● खूब आराम करें।

● खूब तरल पेय पिएं।

● कोल्ड और फ्लू वायरस की वजह से होते हैं, इसलिए इनमें एंटीबायटिक मदद नहीं करतीं।

● इस दौरान जरूरत से ज्यादा कसरत न करें।

● अमूमन कोल्ड या फ्लू होने से पहले गला खराब हो जाता है।

इस दौरान ● गर्म कढ़ी, चाय, कॉफी या गुनगुना नींबू पानी व शहद सिप करने से आराम मिलता है।

● हर आधा घंटे में नमक डालकर गुनगुने पानी से गरारे करने से दर्द और बेचैनी से राहत मिलती है।

● कोल्ड के जाने के बाद भी नाक आना और नाक बंद रहने का अहसास रहता है।

गेहूं चोकर में पोषक तत्वों का महत्व

गेहूं का चोकर प्रोटीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, नियासिन, फास्फोरस, जस्ता एवं विटामिन बी का समृद्ध स्रोत होता है। इसमें वसा की मात्रा कम होती है, जबकि यह कोलेस्ट्रॉल, शर्करा एवं सोडियम रहित होता है। इन्हीं कारणों से यह आंत के कार्य को सामान्य बनाए रखने, रक्त शर्करा एवं कोलेस्ट्रोल की मात्रा को कम करने में मदद करता है। खान-पान की आदतों में बदलाव के कारण होने वाली कब्ज में राहत प्रदान करता है।

दैनिक आहार में अनुशंसित मात्रा

एक वयस्क व्यक्ति को गेहूं के चोकर की 20-30 ग्राम प्रति दिन सेवन करने के लिए अनुशंसित है। इसकी शुरूआत कम मात्रा से की जानी चाहिए। दिन में एक या दो चम्मच ही पर्याप्त है।

गेहूं चोकर के सेवन से स्वास्थ्य लाभ

मोटापे से निजात :

दैनिक आहार में कार्यात्मक फाइबर शामिल करना चाहिए। फाइबर से भरपूर गेहूं की चोकर को सुबह की स्मूदी तथा दही के साथ सेवन करने से शारीरिक वजन कम करने में मदद मिलती है।

बीमारियों को जोखिम कम करता है

उच्च फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से कोलोन कैंसर, हृदय रोग एवं मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम को कम करने में मददगार है।

आंत की बीमारियों में फायदेमंद

संवेदनशील आंत की बीमारी (दस्त/कब्ज के साथ पेट में दर्द) के प्रारम्भिक उपचार के लिए दैनिक आहार में उच्च फाइबर युक्त भोजन का सेवन करने से आराम मिलता है। भोजन में गेहूं की चोकर शामिल करने से फाइबर की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। डायवर्टिकुलर रोग के लक्षण प्रतीत होने पर 45 ग्राम कच्चे असंसाधित गेहूं के चोकर का सेवन करने से आराम मिलता है।

कब्ज से राहत

महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान गेहूं चोकर का सेवन कब्ज को कम करने के साथ मल निष्कासन की आवृत्ति को बढ़ाता है।

हृदय रोग प्रतिरोधी

गेहूं की चोकर में फाइटोकेमिकल एवं एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसलिए, गेहूं का चोकर समावेशित अनाज वाले खाद्य पदार्थों का सेवन हृदय रोगों को रोकने में मदद करता है। गेहूं की चोकर घुलनशील लिपिड यौगिक एवं फाइटो केमिकल्स जैसे- फाइटेट्स, फाइटोस्टेरॉल, टोकोफेरोल आदि का भी एक समृद्ध स्रोत है। इनमें से फाइटेट्स कोलोन कैंसर की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मधुमेह से राहत

फाइबर युक्त सभी प्रकार के फल मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। लेकिन शरीर में इसकी आपूर्ति के लिए गेहूं का चोकर एक बेहतरीन माध्यम है।

आंखों के लिए फायदेमंद

गेहूं का चोकर मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत है, जो मस्तिक, हृदय, आँख और नर्व को स्वस्थ रखने के साथ-साथ हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है।

एंटीऑक्सीडेंट के रूप में

गेहूं के चोकर में सेलेनियम प्राकृतिक रूप में अच्छी मात्रा में होता है, जो मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। हमारे शरीर को इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर में सेलेनियम की संतुलित मात्रा हार्ट अटैक, कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस एवं अस्थमा जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। यह शरीर में उपस्थित टॉक्सिन को बाहर निकालने, प्रतिरोधक क्षमता एवं प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में भी मददगार है।

घर की रसोई में गेहूं के चोकर का उपयोग

गेहूं चोकर का स्वाद मीठा होता है, लेकिन यह देखने में आकर्षक नहीं लगता है। इसको खाने में थोड़ा-थोड़ा उपयोग लाभदायक है, लेकिन थोड़ी सी अधिक मात्रा दस्तावर हो सकती है। मफिन्स, बिस्कुट, ब्रेड, पैनकेक, नूडल्स, स्नैक्स बन्स, वॉफले, कुकीज एवं केक आदि में गेहूं का चोकर मिलाकर पोषण गुणवत्ता एवं आहार रेशा की मात्रा बढ़ाने का बेहतर विकल्प है।

इसके महीन पाउडर की थोड़ी सी मात्रा के उपयोग से स्मूदीज को और अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। शोध दर्शाते हैं कि तले हुए अनाज उत्पादों जैसे पूड़ी के आटे में 3 प्रतिशत गेहूं की चोकर को शामिल करने से पूड़ियाँ तलने में 20 प्रतिशत तेल की बचत होती है।

गेहूं चोकर के उपयोग में सावधानियाँ

गेहूं चोकर में फाइबर एवं ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए अधिक मात्रा में इसका सेवन पेट दर्द का कारण बन सकता है। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है, उन्हें चोकर के सेवन करने से बचना चाहिए।

एलोवेरा: गुणों का खजाना

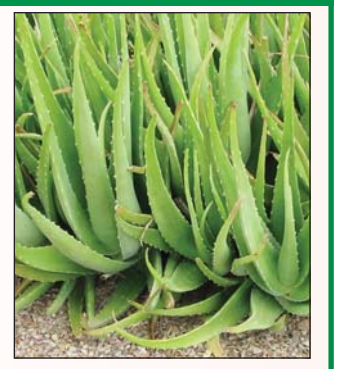

भारत में ग्वारपाठा या घृतकुमारी हरी सब्जी के नाम से प्राचीनकाल से जाना जाने वाला कांटेदार पत्तियों वाला पौधा है, जिसमें रोग निवारण के गुण कूट–कूट कर भरे पड़े हैं। आयुर्वेद में इसे घृतकुमारी की उपाधि मिली हुई है तथा महाराजा का स्थान दिया गया है। औषधि की दुनिया में इसे संजीवनी भी कहा जाता है। इसकी 200 जातियां होती हैं, परंतु प्रथम 5 ही मानव शरीर के लिए उपयोगी हैं।

इसकी बारना डेंसीस नाम की जाति प्रथम स्थान पर है। इसमें 18 धातु, 15 एमीनो एसिड और 12 विटामिन मौजूद होते हैं। इसकी तासीर गर्म होती हैं। यह खाने में बहुत पौष्टिक होता है। इसे त्वचा पर लगाना भी उतना ही लाभप्रद होता है। इसकी कांटेदार पत्तियों को छीलकर एवं काटकर रस निकाला जाता है। 3–4 चम्मच रस सुबह खाली पेट लेने से दिन–भर शरीर में शक्ति व चुस्ती–स्फूर्ति बनी रहती है।

जलने पर, अंग कहीं से कटने पर, अंदरूनी चोटों पर एलोवेरा अपने एंटी बैक्टेरिया और एंटी फंगल गुण के कारण घाव को जल्दी भरता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। बवासीर, डायबिटीज, गर्भाशय के रोग, पेट की खराबी, जोड़ों का दर्द, त्वचा की खराबी, मुंहासे, रूखी त्वचा, धूप से झुलसी त्वचा, झुर्रियों, चेहरे के दाग–धब्बों, आंखों के काले घेरों, फटी एड़ियों के लिए यह लाभप्रद है। इसका गूदा या जैल निकालकर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए। बाल काले, घने–लंबे एवं मजबूत होंगे। यह मच्छर से भी त्वचा की सुरक्षा करता है। आजकल सौन्दर्य निखार के लिए हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद के रूप में बाजार में एलोवेरा जैल, बॉडी लोशन, हेयर जैल, स्किन जैल, शैंपू, साबुन, फेशियल फोम, और ब्यूटी क्रीम में हेयर स्पा में ब्यूटी पार्लरों में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। कम से कम जगह में, छोटे–छोटे गमले में एलोवेरा आसानी से उगाया जा सकता है। एलोवेरा जैल या ज्यूस मेहंदी में मिलाकर बालों में लगाने से बाल चमकदार व स्वस्थ होंगे। एलोवेरा के कण–कण में सुंदर एवं स्वस्थ रहने के कई–कई राज छुपे पड़े हैं। यह संपूर्ण शरीर का कायाकल्प करता है।

पाक्षिक पंचांग

6 से 19 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत् 2082
आश्विन शुक्ल 14 से कार्तिक कृष्ण 13 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार
6	अक्टूबर	सोम	आश्विन शुक्ल	14 शरद पूर्णिमा, पंचक
7	अक्टूबर	मंगल	----------	15 स्ना.दा. पूर्णिमा पंचक 3.18 रात तक
8	अक्टूबर	बुध	कार्तिक कृष्ण	1/2
9	अक्टूबर	गुरु	----------	3
10	अक्टूबर	शुक्र	----------	4 करवा चौथ व्रत
11	अक्टूबर	शनि	----------	5
12	अक्टूबर	रवि	----------	6 स्कंध षष्ठी व्रत
13	अक्टूबर	सोम	----------	7
14	अक्टूबर	मंगल	----------	8
15	अक्टूबर	बुध	----------	9
16	अक्टूबर	गुरु	----------	10
17	अक्टूबर	शुक्र	----------	11 रंभा एकादशी
18	अक्टूबर	शनि	----------	12 प्रदोष व्रत, धनतेरस
19	अक्टूबर	रवि	----------	13 शिव चतुर्थी व्रत

मक्का की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण

उदयपुर। गत दिनों एमपीयूएटी में संचालित अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत सांगवा ग्राम में मक्का की उन्नत खेती के लिए एक दिवस मक्का प्रक्षेत्र दिवस मनाया गया जिसमें विभिन्न गांव से पधारे 100 किसानों ने भाग लिया इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. शंकर लाल जाट (भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, लुधियाना), डॉ. आर. एल. सोनी (निदेशक प्रसार शिक्षा), डॉ. अमित दाधीच (परियोजना प्रभारी, डॉ. जवाला जिंदल, कीट वैज्ञानिक (पंजाब कृषि विश्विद्यालय, लुधियाना), डॉ. मलिका अर्जुन पादप एवं रोग वैज्ञानिक (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, केंद्र माडिया), डॉ. आई. सुधीर कुमार प्लांट ब्रीडर, आंध्र प्रदेश, डॉ. सुमेरिया, सस्य विज्ञान वैज्ञानिक, डॉ. रमेश बाबू कीट वैज्ञानिक, डॉ. राम नारायण कुम्हार, सूत्रकृमि, पादप एवं रोग वैज्ञानिक, प्रह्लाद सिंह झाला कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान सरकार।

डॉ. दाधीच ने सभी कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों का स्वागत किया और विश्वविद्यालय द्वारा नई किस्म का विस्तृत से वर्णन किया और मक्का को मेवाड़ की मुख्य फसल बताया किसानों को अधिक उगाने के प्रेरित किया। डॉ. हरीश कुमार सुमेरिया ने मक्का की प्रथम पंक्ति दर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉ. ज्वाला जिंदल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मक्का में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

साथ ही कर्नाटक से पधारे डॉ. मल्लिकार्जुन ने मक्का में लगने वाले रोग के नियंत्रण के बारे में सम्पूर्ण किसानों हितोप्योगी जानकारी दी। आई. सुधीर कुमार आंध्र प्रदेश ने प्रदेश में किस प्रकार मक्का की उन्नत खेती की जाती है उसके बारे में बताया।

डॉ. आर.एल सोनी प्रसार निदेशक ने किसानों को मक्का के साथ साथ अन्य साधनों से की प्रकार किसानों की आमदनी दुगनी कैसे बढ़ायें उसकी विस्तृत जानकारी दी। डॉ. राम नारायण कुम्हार, सूत्रकृमि, पादप एवं रोग वैज्ञानिक ने मक्का में लगने वाले कीट,सूत्रकृमि एवं रोग की पहचान उपयुक्त समय में सही दवाई का इस्तेमाल करने के बारे में बताया। डॉ. शंकर लाल जाट, प्रधान मक्का वैज्ञानिक, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना ने मक्का की उन्नत खेती में आने वाली समस्याओं व उनके समाधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी, साथ ही मक्का से बनने वाले विभिन्न उत्पादों, किसान अपने खेत में किस प्रकार मक्का की उन्नत किस्म को तैयार करें, और बाजार में किस प्रकार बेचे इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी।

'सहकार सदस्यता अभियान' 641 पैक्स में हुआ शिविरों का आयोजन

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे 'सहकार सदस्यता अभियान' के तीसरे दिन प्रदेश भर में 641 पैक्स के स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में आमजन और सहकार बंधुओं की बड़ी संख्या में भागीदारी हो रही है और सहकारिता विभाग से संबंधित कार्य अभियान के माध्यम से तीव्र गति से सम्पन्न हो रहे हैं।

अभियान के अंतर्गत प्रारम्भिक तीन दिवसों में 1,682 पैक्स में शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में 'ग्रामीण सेवा शिविरों' के अंतर्गत अभियान से संबंधित गतिविधियां संपादित की जा रही हैं। प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी जनसाधारण को उपलब्ध करवाना 'सहकार सदस्यता अभियान' के अंतर्गत एक प्रमुख गतिविधि है। शिविरों में आमजन को पम्पलेट वितरण तथा विचार-विमर्श सत्रों के माध्यम से नवीन कानून के प्रावधानों से अवगत करवाया जा रहा है। शनिवार को आयोजित शिविरों में 20 हजार से अधिक लोगों को प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून की जानकारी प्रदान की गई। अब तक 1.90 लाख से अधिक लोगों को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से अवगत करवाया जा चुका है।

इसी प्रकार, अभियान के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लम्बित आवेदनों में से 16 हजार 432 पात्र कृषकों की आधार सीडिंग तथा 7,748 पात्र कृषकों की ई-केवाईसी का कार्य किया जा चुका है। प्रदेश में वर्तमान में 2,173 ग्राम पंचायतें पैक्सविहीन हैं, जिनमें से 1,340 में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा 837 पैक्स के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठकें भी आयोजित हो चुकी है। अभियान के अंतर्गत नवीन पैक्स गठन की प्रक्रिया तेज गति से पूरी की जा रही है। वहीं, गोदाम निर्माण हेतु 1,141 पैक्स एवं केवीएसएस द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया जा चुका है। अभियान के अंतर्गत सहकारी समितियों से अधिक से अधिक नये सदस्य जोड़ने के लिए भी पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं।

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-

- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि
- बीज ▪ औषधीय फसल

विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक

- अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.

कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेवल्स, तीर्थ यात्रायें, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
(सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक)
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagat
@krishakjagatindia @krishak_jagat

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
⇨ वार्षिक रु. 600/- ⇨ दो वर्ष रु. 1000/-
⇨ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम .....पो. .....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

आईसीएआर की अ.भा. प्रतियोगी परीक्षा से भरी जाएंगी

कृषि विश्वविद्यालयों की 20 प्रतिशत स्नातक सीटें

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि विद्यार्थियों की समस्या का किया समाधान

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि शिक्षा से संबंधित एक गंभीर मुद्दे को हल करते हुए कृषि के छात्र-छात्राओं तथा उनके पालकों को बड़ी राहत दी है। अब कृषि विश्वविद्यालयों की 20 प्रतिशत स्नातक सीटें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी, जिसमें 'एक देश-एक कृषि-एक टीम' की भावना के अनुरूप, देशभर के छात्रों के लिए पात्रता मानदंड एवं विषय समूह को एक समान कर दिया गया है, जिससे 12वीं में बायोलॉजी, रसायन, भौतिकी, गणित या कृषि विषय समूह लेने वाले विद्यार्थी बराबर पात्रता के साथ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी-आईसीएआर) के जरिये सीधे-पारदर्शी तरीके से दाखिला ले सकेंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि कृषि स्नातक (B.Sc. Agri) में, प्रवेश में कुछ वर्षों से एक बड़ी समस्या छात्र-छात्राओं के लिए अक्षम पात्रता मानदंड की थी, 12वीं में अलग-अलग विषय संयोजनों (कृषि, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स) तथा अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियमों, अलग-अलग पात्रता के कारण कृषि के ये योग्य छात्र-छात्राएं पिछड़ जाते थे। इस बारे में पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों ने समस्या बताई थी, वहीं कुछ राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने भी केंद्रीय मंत्री श्री चौहान को इस संबंध में लिखा था, जिस पर उन्होंने संवेदना के साथ तुरंत संज्ञान लिया व विद्यार्थियों की समस्या को गंभीरता से समझकर आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट को निर्देश दिया कि वे राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों एवं उनके कुलपतियों के साथ बातचीत करके इसका त्वरित हल ढूंढने की दिशा में काम करें।

महिंद्रा ने सितम्बर में 65 हजार ट्रैक्टर बेचे

मुंबई (कृषक जगत)। महिंद्रा समूह के हिस्से, महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस (एफईबी) ने सितंबर 2025 के लिए अपने ट्रैक्टर बिक्री आंकड़ों की घोषणा की। सितंबर 2025 में घरेलू बिक्री 64,946 इकाई थी, जबकि सितंबर 2024 में 43,201 इकाई थी, जो ग्राहकों को जीएसटी में कमी के लाभ और पिछले साल की त्योहारी अवधि की तुलना में इस साल नवरात्रि को सितंबर में आगे बढ़ाने के कारण 50 प्रतिशत साल-दर-साल वृद्धि को दर्शाती है। सितंबर 2025 के दौरान कुल ट्रैक्टर बिक्री (घरेलू + निर्यात) 66,111 इकाई रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 44,256 इकाई थी। इस महीने निर्यात 1,165 इकाई रहा।

प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, **महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. के कृषि उपकरण व्यवसाय के अध्यक्ष, श्री विजय नाकरा** ने कहा, 'हमने सितंबर के दौरान घरेलू बाजार में 64,946 ट्रैक्टर बेचे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी दरों में कटौती के फैसले से, पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल सितंबर महीने में नवरात्रि में बिक्री में वृद्धि हुई। खरीफ की सकारात्मक संभावनाओं, इस मौसम में बुआई के रकबे में वृद्धि और सामान्य से बेहतर मानसून जैसे कारकों ने इसे और मजबूत किया है।'

निजी आवासीय छतों पर होगी सब्जी की खेती

जयपुर में शुरू हुई 'स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना'

जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आईएसआईटीसी), दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्र में स्थित निजी आवासों की छतों पर सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना' की शुरुआत की गई है।

इस योजना के अंतर्गत केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों के स्वामी ही आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान या अन्य गैर-आवासीय भवन इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

रूफ टॉप यूनिट निर्माण की कुल अनुमानित लागत 53 हजार 619 रूपए है। इसमें से 70 प्रतिशत(37हजार 534 रूपए) की राशि अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहन की जाएगी जबकि शेष 30 प्रतिशत (16 हजार 085 रूपए) राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी।परियोजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक 1 अक्टूबर से

31 अक्टूबर 2025 तक पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी और आवेदन पत्र संस्थान के कार्यालय से ही प्राप्त किए जा सकेंगे। योजना के दिशा-निर्देश, पात्रता की शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप आईएसआईटीसी, दुर्गापुरा, जयपुर से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष संख्या 9636839317 पर कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।

इफको का नया जैव उत्तेजक 'धराअमृत'

किसानों को जलवायु चुनौतियों से लड़ने में करेगा मदद

इफको ने कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपना नवीनतम जैव उत्तेजक (बायो-स्टिमुलेंट) 'धराअमृत' लॉन्च किया है। यह उत्पाद विशेष रूप से किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ाने और पौधों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक रूप से विकसित किया गया है। 'धराअमृत' में अमीनो एसिड, एल्जिनिक एसिड, कार्बन और जरूरी सूक्ष्म खनिज शामिल हैं, जो उन्नत कॉलॉइडल प्रोसेसिंग तकनीक से तैयार किए गए हैं। यह जैव उत्तेजक पौधों के चयापचय को नियंत्रित करता है, कोशिकाओं की संरचना मजबूत करता है और पौधों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 'धराअमृत' जैविक खेती को नया आयाम देगा और किसानों को मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगा। इसके उपयोग से न केवल फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि संभव होगी। इफको का यह कदम आधुनिक, वैज्ञानिक कृषि की दिशा को और मजबूत करेगा और भारतीय कृषि को टिकाऊ बनाएगा।

उपयोग की विधि और मात्रा

'धराअमृत' को किसानों द्वारा कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ोलियर स्प्रे के रूप में एक एकड़ क्षेत्र में 500 मिलीलीटर की मात्रा में छिड़काव किया जाना चाहिए। ड्रिप फर्टिगेशन में इसे 1 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ड्रोन स्प्रे के लिए 500 मिलीलीटर 'धराअमृत' को 9.5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है। यह नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, फोलियर न्यूट्रिएंट्स, कीटनाशक और फंगीसाइड्स के साथ पूरी तरह से संगत है।

लॉन्च इवेंट और प्रमुख उपस्थित लोग

'धराअमृत' के लॉन्च कार्यक्रम में गुजरात सरकार के कृषि मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा, सांसद श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप सांघानी, प्रबंध निदेशक श्री के. जे. पटेल, इफको-नैनोवेंशन्स के एमडी डॉ. ए. लक्ष्मणन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के किसान भी इस मौके पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम ने कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को अपनाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए इफको की प्रतिबद्धता को दोहराया।

धराअमृत के फायदे

- फसलों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता में वृद्धि
- पौधों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार
- फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी
- सभी प्रकार के फोलियर पोषक तत्वों के साथ पूरी तरह संगत
- विभिन्न फसल प्रणालियों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है

ग्रोमैक्स ने 8 नए ट्रैक्टर लॉन्च किए

मुंबई (कृषक जगत)। महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. और गुजरात सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम ग्रोमैक्स एग्री इक्विपमेंट लि. ने 4WD और 2WD श्रेणियों में ट्रैक स्टार सीरीज के 8 नए ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं, जिसमें 50 एचपी से कम सेगमेंट में भारत की पहली फैक्ट्री-फिटेड केबिन श्रृंखला शामिल है।

ग्रोमैक्स के नए ट्रैक्टर बेहतरीन प्रदर्शन और संचालन में आसान हैं, जो खेती की सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये नए ट्रैक्टर बाग की खेती, सुपारी की खेती, अंतर-खेती, पडलिंग और ढुलाई जैसे कार्यों को पूरा करेंगे। अपनी ट्रैक स्टार कवच श्रृंखला के अंतर्गत, ग्रोमैक्स ने 50 एचपी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों में भारत की पहली फैक्ट्री-फिटेड केबिन श्रृंखला पेश की है, जिसे किसानों को सुरक्षित, आरामदायक और मौसम-रोधी कार्यस्थल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, **महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. के कृषि उपकरण व्यवसाय के अध्यक्ष श्री विजय नाकरा** ने कहा, 'ग्रोमैक्स में हमें एक ही दिन में आठ नए ट्रैक्टरों का अनावरण करने पर गर्व है। त्योहारी सीजन के साथ, नए ट्रैक्टर अक्टूबर 2025 से ग्रोमैक्स डीलरशिप पर उपलब्ध होंगे। त्योहारी सीज़न के दौरान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रोमैक्स डीलर एक विशेष उपभोक्ता योजना और हर ट्रैक्टर खरीद पर एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं।

राष्ट्रीय दलहन मिशन को मंजूरी

11,440 करोड़ रु. का बजट, लेकिन किसानों की मुनाफेदारी पर सवाल

(नई दिल्ली से निमिष गंगराड़े)

नई दिल्ली (कृषक जगत)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय दलहन मिशन को मंजूरी दे दी है। साथ ही, सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य- एमएसपी में भी वृद्धि की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, पोषण सुरक्षा को मज़बूत करना और किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है। सरकार ने वर्ष 2030-31 तक 35 मिलियन टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो 2024-25 में अनुमानित 24.2 मिलियन टन से लगभग 45 प्रतिशत अधिक है।

मिशन की रूपरेखा: 416 जिलों में लागू होगा, 100 प्रतिशत सरकारी खरीद की गारंटी

राष्ट्रीय दलहन मिशन देश के 416 जिलों में लागू किया जाएगा। इसके तहत-

- धान की परती ज़मीनों का उपयोग
- उन्नत किस्मों के बीजों का प्रचार
- अंतरवर्तीय फसलें
- सूक्ष्म सिंचाई सहायता
- अरहर, उड़द व मसूर जैसी दालों की 100 प्रतिशत सरकारी खरीद जैसे कदम शामिल हैं।
- सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए रु. 11,440 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।

किसानों की चुनौती: एमएसपी बढ़ा, पर लागत उससे तेज़।

योजना आकर्षक दिखती है : एमएसपी में वृद्धि और सरकारी खरीद की गारंटी दोनों हैं।

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या किसानों का मुनाफ़ा वाकई बढ़ेगा? विशेषज्ञों के अनुसार, दलहन खेती की लागत हर साल 8-12 प्रतिशत तक बढ़ रही है, जबकि इस बार एमएसपी वृद्धि केवल 4-6 प्रतिशत तक सीमित रही है। खाद, बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, सिंचाई और मशीनरी सभी में बढ़ती महंगाई ने किसानों की लाभ मार्जिन को घटा दिया है।

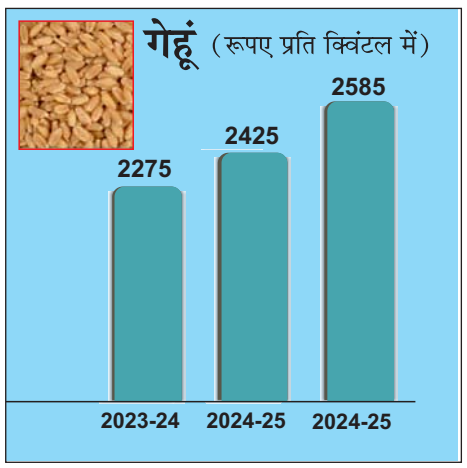

एक कृषि अर्थशास्त्री के शब्दों में

- 'मुद्दा केवल एमएसपी बढ़ाने का नहीं है।
- असली समाधान तब मिलेगा जब उत्पादकता लागत से तेज बढ़े।
- जब तक बीज तकनीक, मशीनीकरण और लागत-कुशलता में सुधार नहीं होगा, दलहन मिशन किसानों की स्थायी आय की बजाय एक और सब्सिडी योजना बनकर रह जाएगा।

तिलहन बनाम दलहन: नीति में असमान संतुलन

आंकड़े बताते हैं कि सरकार का झुकाव तिलहन और मोटे अनाजों की ओर अधिक है।

जैसे- सरसों और रेपसीड का एमएसपी 4.2 प्रतिशत, जबकि मसूर का केवल 4.48 प्रतिशत और चने का 3.98 प्रतिशत बढ़ाया गया है। वहीं कुसुम (सैफ्लॉवर) की एमएसपी वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक रही है। इससे सवाल उठता है कि अगर प्रोत्साहन बराबर नहीं, तो क्या सरकार दलहन उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर पाएगी?

स्पष्ट है कि सबसे अधिक समर्थन तिलहन फसलों को मिला है, जबकि दलहन में वृद्धि सीमित रही।

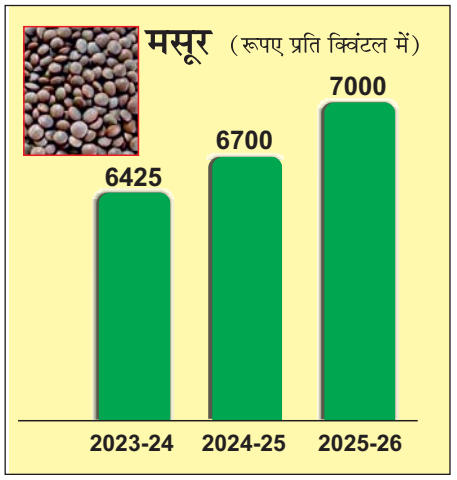

मिशन बड़ा है, पर किसान की आय पर चिंता बरकरार

राष्ट्रीय दलहन मिशन निश्चित रूप से पोषण सुरक्षा और आयात घटाने की दिशा में बड़ा कदम है।

11,440 करोड़ रु. का बजट, ज़िला-स्तरीय कार्ययोजना और सरकारी खरीद की गारंटी - ये सभी कदम महत्वपूर्ण हैं। फिर भी किसानों की मूल समस्या बनी हुई है -लागत एमएसपी से तेज बढ़ रही है।

एमएसपी बढ़ने से किसानों को कुछ राहत जरूर है, लेकिन स्थायी लाभ तभी मिलेगा जब उत्पादकता, तकनीक और सिंचाई दक्षता पर समान ध्यान दिया जाए।

दलहन मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार केवल 'कीमत और खरीद' तक सीमित न रहे, बल्कि बीज गुणवत्ता, अनुसंधान, लागत प्रबंधन और मूल्य स्थिरता पर समान रूप से ध्यान दे। तभी किसान को वास्तविक मुनाफ़ा मिलेगा और भारत सच में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाएगा।

एमएसपी वृद्धि तुलना (विपणन वर्ष 2025-26 बनाम 2026-27)

फसल	2025-26 (रु./क्विं.)	2026-27 (रु./क्विं.)	वृद्धि (रु.)	वृद्धि (प्रतिशत)
गेहूं	2,425	2,585	160	6.60
जौ	1,980	2,150	170	8.59
चना	5,650	5,875	225	3.98
मसूर	6,700	7,000	300	4.48
रेपसीड और सरसों	5,950	6,200	250	4.20
कुसुम (सैफ्लॉवर)	5,940	6,540	600	10.10

सर्वोत्तम गुणवत्तावाली
जैन ड्रिप की विस्तृत उत्पादन श्रृंखला -
सभी फसलों# के लिए हर किसान के बजट के
अनुरूप विभिन्न प्रकार के ड्रिप सिंचाई व्यवस्था
के विकल्प स्टॉक में उपलब्ध हैं।
(# दलहन, धान, तिलहन, सब्जियाँ एवं फल बागानें आदि के लिए)

जैन टर्बो स्लिम - टीई व सुपर सेव्हर
5 से 20 मील (0.13 से 0.5 मिमी)
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन टर्बो एक्सेल प्लस
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन टर्बो लाईन सुपर
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी साईज

जैन टर्बो लाईन - पीसी
क्लास २
साईज - १६, २० मिमी

जैन टर्बो टॉप - एचडी पीसी
१३, १५ मील (०.33, ०.38 मिमी) - क्लास 1 व 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन पॉलीट्यूब एवं ड्रिपर्स
साईज - 12, 16, 20, 25, 32 मिमी

नोट : ड्रिपर्स व ड्रिपलाईन अलग-अलग प्रेशर रेटींग में उपलब्ध

जैन ड्रिप® प्रति बूंद, फसल भरपूर!®
जैन™ जैन इरिगेशन सिस्टम्स् लि. छोटे छोटे कदम. आसमान छूने का दम!®
दूरभाष: 0257-2258011; 6600800
टोल फ्री : 1800 599 5000
ई-मेल: jisl@jains.com; वेबसाईट: www.jains.com

ड्रिपलाईन व फिटींग्ज | ड्रिपर्स | रेनपोर्ट स्प्रिंकलर | स्प्रे हेड व जेटस् | वॉल्व | फिल्टर्स | फिल्ट्रेशन संसाधन | फर्टिगेशन संसाधन | पीव्हीसी पाईप व फिटींग्ज | एचडीपीई पाईप्स व फिटींग्ज | क्विक कनेक्ट पाइप | ऑटोमेशन व कन्ट्रोलर्स

सावधान! नकल करके ड्रिप बनाने वाले एवं
नकली ड्रिप कंपनियों और वितरकों से सतर्क रहें!